राजीव नारायण रैना, जे,

ईश कुमार- याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य हरियाणा और अन्य-उत्तरदाता

सीडब्ल्यूपीएनओ.एल4447ऑफ20एच

अगस्त8,20J3

भारत का संविधान, *1950* - अनुच्छेद *227*- पंजाब पुलिस नियम, *1934* - *Rl. 16.21* - याचिकाकर्ता ने *1.4.2008* से *31.3.2009* की अवधि के लिए अपनी एसीआर में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की, जिस अवधि के दौरान वह आईजी पुलिस के नियंत्रण में हरियाणा पुलिस अकादमी में तैनात था - याचिकाकर्ता को एक घटना के कारण *6.6.2008* को निलंबित कर दिया गया और उसे निंदा की सजा दी गई - याचिकाकर्ता का तर्क कि निलंबन की तारीख तक, उन्होंने आईजी पुलिस के अधीन *3* महीने से कम समय तक काम किया था, और इसलिए, निर्देशों और परिपत्रों के अनुसार, आईजी पुलिस नहीं कर सकते थे

आरएल *16.21*, आरपीआर के अनुसार, एक निलंबित पुलिस अधिकारी कानून और व्यवस्था और जांच के रखरखाव के संबंध में एक पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है - याचिकाकर्ता को प्रशिक्षुओं की इनडोर कक्षाएं लेने का काम सौंपा गया था और पंजाब पुलिस अधिनियम के तहत अनुशासन के अधीन था और आईजी पुलिस के पास उसके निलंबन के बाद भी याचिकाकर्ता के काम और आचरण को देखने का अवसर था, हालांकि एक अलग भूमिका में - आक्षेपित आदेश को बरकरार रखा गया, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

यह माना गया कि पंजाब पुलिस पुलेस, 1934 के तहत निलंबित पुलिसकर्मी की स्थिति हरियाणा पर लागू सिविल कर्मचारियों से अलग है। एक निलंबित पुलिस अधिकारी एक पुलिस अधिकारी बनना बंद नहीं करता है और वह उसी जिम्मेदारियों, अनुशासन और दंड के अधीन रहता है जैसे कि उसे निलंबित नहीं किया गया था। वह पीपीआर के नियम 16.21 पर भरोसा करता है जो यह प्रदान करता है कि निलंबित पुलिसकर्मी उसी जिम्मेदारी, अनुशासन और आचरण के अधीन रहता है जैसे कि उसे निलंबित नहीं किया गया था। यह केवल इतना है कि निलंबन के दौरान वह कानून और व्यवस्था के रखरखाव और अपराध की जांच में एक पुलिस अधिकारी के रूप में कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है।

(पैरा 4)

बर (उनका मानना है कि इन परिस्थितियों में, मैं कार्यकारी निर्देशों का लाभ देने के लिए तैयार नहीं हूं और यह मानूंगा कि वर्तमान मामले में एक या दूसरे रूप में याचिकाकर्ता के काम और आचरण को तीन महीने से अधिक समय तक देखा गया था, और किसी भी मामले में इस तरह के निर्देश प्रकृति में कम या ज्यादा निर्देशिका हैं और पंजाब पुलिस नियमों के तहत निर्धारित वैधानिक नियमों का हिस्सा नहीं हैं, 1934 हरियाणा के लिए यथा लागू। यहां तक कि यह मानते हुए कि आईजी/पीसीएसआर का विचार माना जाता है कि टिप्पणियों को हटा दिया जाना चाहिए, तब भी मुझे लगता है कि अंतिम प्राधिकारी यानी ए.सी.ए.जी.पी./प्रशासन का निर्णय न तो विकृत है और न ही मनमाना है कि उनकी राय में प्रतिकूल टिप्पणी केवल इस तथ्य के कारण रहनी चाहिए कि याचिकाकर्ता को कदाचार साबित होने के बाद विभागीय जांच में दंडित किया गया था।

(पैरा 8)

नवीन एस. भारद्वाज, अधिवक्ता, या याचिकाकर्ता।

Harish Rathce, Sr. DAG, Haryana.

राजीव नारायण रैना, जे।

(एक) याचिकाकर्ता हरियाणा पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर ने तत्कालीन पुलिस आयुक्त, गुड़गांव के नियंत्रण और कमान के तहत काम किया और 01.04.2008 से 31.03.2009 की अवधि के लिए अपनी एसीआर में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए इस अदालत से संपर्क किया है। मूल्यांकन की उपरोक्त अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता पुलिस महानिरीक्षक के नियंत्रण में हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन में तैनात था। याचिकाकर्ता ने 01.04.2008 से 06.06.2008 तक काम किया था जब उसे एक घटना में आरोप-पत्र और जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि 24/25.05.2008 की मध्यरात्रि को उसने मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स के सामने चलने वाले एक ढाबे के मालिक को सार्वजनिक रूप से पीटा था। विभागीय जांच उनके विरुद्ध चली गई और उन्हें निन्दा की गई जो छोटी सजा अंतिम है।

(दो) श्री केपी सिंह, आईपीएस तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक अकादमी, मधुबन ने याचिकाकर्ता के काम को 01.04.2008 से 06.06.2008 तक यानी दो महीने और छह दिनों के लिए देखा था और याचिकाकर्ता को औसत के रूप में ग्रेड दिया था। याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि वर्ष 01.04.2008-31.03.2009 के लिए एसीआर में ये टिप्पणियां अनुचित हैं और इस संक्षिप्त आधार पर कार्यवाही से निकाले जाने योग्य हैं कि हरियाणा पर लागू

पंजाब सरकार के परिपत्र दिनांक 03.05.1960 के साथ पठित परफोनुएंस मूल्यांकन, खंड-VI पर दिनांक 21.04.1956 के निर्देश और गोपनीय रिपोर्टों की रिकॉर्डिंग के संबंध में हरियाणा सरकार के पत्र दिनांक 02.03.1971 के अनुसार एक रिपोर्टिंग अधिकारी को कम से कम तीन महीने तक एक अधिकारी के काम और आचरण को देखने की आवश्यकता होती है। इन अनुदेशों को निम्नलिखित के रूप में निर्धारित किया गया है:-

> किसी भी रिपोर्टिंग प्राधिकारी को अपने अधीन आने वाले अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में उनकी टिप्पणी तब तक दर्ज नहीं करनी चाहिए जब तक कि उसने वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम तीन महीने तक अपना काम और आचरण नहीं देखा हो।
>
> व्याख्यात्मक नोट: इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट तीन महीने की अवधि का अर्थ है वह अवधि जिसके लिए रिपोर्टिंग प्राधिकारी ने वास्तव में रिपोर्ट किए गए अधिकारी / अधिकारी के काम को देखा है। रहता है, नियमित छुट्टी (आकस्मिक से अलग
>
> (ख) यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तो निलंबन अवधि, जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, को इस अवधि की गणना में नहीं गिना जाएगा। इसी प्रकार, उस अवधि, यदि कोई हो, जिसके दौरान रिपोटग प्राधिकारी छुट्टी पर है या निलम्बित है, की गणना नहीं की जानी है। "

(तीन) प्रस्ताव जारी होने की सूचना पर, राज्य ने लिखित बयान दर्ज करके अपनी कार्रवाई को सही ठहराया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस महानिरीक्षक, एचपीए, मधुबन रिपोर्टिंग प्राधिकारी थे और स्वीकार करने वाले प्राधिकारी 01.04.2008 से 31.03.2009 की अवधि के लिए वार्षिक गोपनीय रोल के संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, 1 लारियाना थे और पुलिस आयुक्त, गुड़गांव नहीं थे जहां उन्हें प्रासंगिक अवधि के दौरान तैनात किया गया था। मधुबन में याचिकाकर्ता के ढाबा मालिक से जुड़ी घटना में उनके आचरण और सार्वजनिक रूप से उनकी पिटाई के खिलाफ लगाए गए आरोप विभागीय जांच में साबित हुए हैं, जिसके लिए उन्हें निंदा के साथ दंडित किया गया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने विभागीय जांच के दौरान सहयोग नहीं किया और कार्यवाही में देरी करने के लिए अपनी तैनाती के स्थान पर अनुपस्थित रहा।

(चार)श्री रठक ने आग्रह किया कि पंजाब पुलिस नियम, 1934 के तहत निलंबित पुलिसकर्मी की स्थिति जो हरियाणा पर लागू है, सिविल कर्मचारियों से अलग है। एक निलंबित पुलिस अधिकारी एक पुलिस अधिकारी बनना बंद नहीं करता है और वह उसी जिम्मेदारियों, अनुशासन और दंड के अधीन रहता है जैसे कि उसे निलंबित नहीं किया गया था। पीपीआर के नियम 16.21 पर मुझे अवशेष हैं जो यह प्रदान करता है कि निलंबित पुलिसकर्मी उसी जिम्मेदारी, अनुशासन और आचरण के अधीन रहता है जैसे कि उसे निलंबित नहीं किया गया था। यह केवल इतना है कि निलंबन के दौरान वह कानून और व्यवस्था के रखरखाव और अपराध की जांच में एक पुलिस अधिकारी के रूप में कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है।

(पाँच) यह माना जाता है कि निलंबन के दौरान याचिकाकर्ता को हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन के इनडोर स्टाफ में तैनात किया गया था और प्रशिक्षुओं की इनडोर कक्षाएं लेने और ऐसे अन्य विविध कार्यों को पूरा करने के लिए ड्यूटी सौंपी गई थी, जो उसे सौंपे गए थे, लेकिन जहां पुलिस अधिकारी के रूप में उसकी शक्ति के

प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए, यह कहना गलत है कि पुलिस महानिरीक्षक ने उनके काम और आचरण को देखा

केवल 2 महीने और 6 दिनों के लिए और मूल्यांकन की पूरी अवधि के लिए नहीं, हालांकि भूमिका 06.06.2008 से अलग थी जब याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था। इसलिए, एसीआर में दर्ज की गई टिप्पणी श्री रथकबे के अनुसार विशुद्ध रूप से 2 महीने और 6 दिनों के दृष्टिकोण से नहीं देखी जा सकती है या निर्देशों के उल्लंघन के कारण न्यूनतम तीन महीने के व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता होती है। जब तक वही पुलिस महानिरीक्षक कर निर्धारण की अवधि के दौरान अपने पद पर बना रहेगा तब तक न्यूनतम तीन माह के जोखिम को निर्धारित करने वाले अनुदेश निर्देशात्मक प्रकृति के होंगे न कि अनिवार्य होंगे।

(छः) "इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिकृति पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया है जिसमें उसने आरटी 1 के तहत प्राप्त नोटिंग शीट पर भरोसा किया है, जो बताता है कि फाइल की जांच करते समय विभिन्न ऑडियोरिटी ने 90 दिनों से कम अवधि के कारण टिप्पणियों को हटाने की सिफारिश की थी। श्री के एस क्लावराज, आईपीएस आईजीपी/पर्सन ने एआईजी/प्रशासन द्वारा दिनांक 09-04-2010 को व्यक्त किए गए इस विचार से सहमति व्यक्त की कि टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए। जब यह मामला एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणियों की एक प्रविष्टि दर्ज करने के मामले में उप निरीक्षकों के लिए अंतिम प्राधिकारी ए डीजी पी/ए डीएम के समक्ष रखा गया था, तो उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच के भाग्य के बारे में पूछते हुए 12.01.2011 को एक प्रश्न पूछा था। तदनुसार, एडीजीपी/प्रशासन को सूचित किया गया था कि निंदा की सजा दी गई है और निलंबन की अवधि को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए ड्यूटी पर बिताए गए समय के रूप में माना गया है। दिनांक 13-06-2011 को सक्षम प्राधिकारी ने अंतिम निर्णय लिया कि चूंकि याचिकाकर्ता को विभागीय जांच में दंडित किया गया है, इसलिए आईजीपी, मधुबन द्वारा रिकार्ड की गई प्रतिकूल टिप्पणियां उस पर कायम रहेंगी। इस अभ्यावेदन को दिनांक 13-06-2011 को अस्वीकृत कर दिया गया। 'चाचू की रसोई के नाम से मशहूर मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी गेट के सामने स्थित एचओटीसीएल/ढाबा के मालिक धन सिंह को पीटने के लिए 10.05.2010 को फ्लिक निंदा की गई थी। औसत की फ्लिक प्रतिकूल टिप्पणी 17.06.2009 को संसूचित की गई थी और एडीजीपी द्वारा 13.06.2011 को लिए गए निर्णय से विधिवत अवगत कराया गया था। जिस कदाचार के लिए याचिकाकर्ता को दंडित किया गया है, वह मूल्यांकन की अवधि के भीतर है, जिसके लिए औसत टिप्पणी दर्ज की गई थी, 'फ्लिक वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां रिपोर्टिंग प्राधिकारी ने 2 महीने और 6 दिनों के लिए एक अधीनस्थ के काम और आचरण को देखा था और उसके बाद उसे तैनात किया गया था या बना हुआ था

ट्रेन भर्ती के दौरान निलंबन के दौरान सौंपे गए कर्तव्यों के मद्देनजर निलंबन के बाद अधीनस्थ के किसी भी संपर्क या ज्ञान या कार्य और आचरण के बिना तैनात किया गया।

(सात) इसके विपरीत, याचिकाकर्ता प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ अपने अभ्यावेदन में स्वीकार करता है जब वह कहता है कि उसका शाखा में तैनात अपने अधीनस्थों पर पूरा नियंत्रण है और इसलिए, एक तरह से वह नियमित मेन लाइन पुलिसिंग के अलावा कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था और इस प्रकार विपरीत रूप से स्वीकार करता है कि उसका काम और आचरण उसके वरिष्ठ की निगरानी में रहा, तत्कालीन आईजीपी मधुबन।

(आठ) इन परिस्थितियों में, मैं कार्यकारी निर्देशों के बेक्लिट को पुन: प्रस्तुत सुप्रा देने के लिए तैयार नहीं हूं और यह मानूंगा कि वर्तमान आसानी से किसी न किसी रूप में याचिकाकर्ता के काम और आचरण को तीन महीने से अधिक समय तक देखा गया था, और किसी भी आसानी से ऐसे निर्देश प्रकृति में कम या ज्यादा

निर्देशिका हैं और पंजाब पुलिस नियमों के तहत निर्धारित वैधानिक नियमों का हिस्सा नहीं हैं, 1934 जैसा कि लारियाना पर लागू होता है। यहां तक कि यह मानते हुए कि आईजी/पीसीएसआर का विचार माना जाता है कि टिप्पणियों को हटा दिया जाना चाहिए, तब भी मुझे लगता है कि अंतिम प्राधिकारी यानी ए.सी.ए.जी.पी./प्रशासन का निर्णय न तो विकृत है और न ही मनमाना है कि उनकी राय में प्रतिकूल टिप्पणी केवल इस तथ्य के कारण रहनी चाहिए कि याचिकाकर्ता को कदाचार साबित होने के बाद विभागीय जांच में दंडित किया गया था। मेरे विचार से, याचिकाकर्ता निंदा के साथ हल्के ढंग से बच गया और कड़ी सजा का हकदार था। मैं उनके दिनांक 14-12-2009 (पी-3) के अभ्यावेदन के माध्यम से गया हूं और पाया है कि आरोपों के साबित होने के बाद हास्यास्पद और ढाबे पर पिटाई करने के मनगढ़ंत आधारों जैसे शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता था। 'मैं संसदीय भाषा नहीं हूं और इसमें संयम की कमी है जिसे आसानी से टाला जा सकता है जब एक सब इंस्पेक्टर वरिष्ठ अधिकारियों को स्मारक सौंपता है। याचिकाकर्ता ने रिपोर्टिंग अधिकारी को नाम से अभियुक्त नहीं बनाया है और इसलिए, उसके खिलाफ पूर्वाग्रह और दुर्भावना पर नहीं सुना जा सकता है। एडीजीपी/एडमिरल के आदेश से याचिकाकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है।

(नौ) प्रश्नाधीन अवधि के लिए प्रतिकूल एसीआर को हटाने का कोई आधार नहीं बनाया गया है।

(दस) याचिका मेरिट से रहित है और खारिज कर दी गई है।

पी.एस., बाजवा

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्णवादी के सीमित उपयोग के लि एहैताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयर्ण का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी,
हरियाणा